Fixed for 02.03.2022

Matter under rule 130 raised by Sh. Vikramaditya Singh , Hon'ble MLA (Shimla Urban)

The House may discuss the irregularities in the implementation of Smart City Project in Shimla City.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

शहर, भारत सहित प्रत्येक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन है। वर्तमान में भारत की लगभग 31 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है और यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (वर्ष 2011 की जनगणना) का 63 प्रतिशत है। शहरीकरण में वृद्वि होने से, शहरी क्षेत्रों से वर्ष 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 75 प्रतिशत होने की संभावना है। इसके लिए भौतिक, संस्थानिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना का व्यापक विकास अपेक्षित है। ये सभी विकास और वृद्वि के सूचक शहरों की ओर लोगों और निवेश को आकर्षित करने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी मिशन की परिकल्पना की गई है।

स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सरंचना तथा स्मार्ट संसाधनों के माध्यमों से अपने नागरिकों को स्वच्छ और सतत वातावरण प्रदान करते है। इसके द्वारा दीर्घकालिक और सम्पूर्ण विकास पर केन्द्रित तथा व्यवस्थित क्षेत्रों को आर्दश मॉडल बनाना है जो अन्य महत्वकांक्षी शहरों के लिए एक प्रकाश स्तभ की तरह कार्य करेगा।

केन्द्र सरकार स्मार्ट सिटी द्वारा अपनाये जाने के लिए किसी मॉडल विशेष का निर्धारण नहीं करती है। दृष्टिकोण "वन–साइज–फिटज–ऑल" का नहीं है; प्रत्येक शहर को स्मार्ट सिटी के लिए अपनी संकल्पना, दर्शन, मिशन और योजना (प्रस्ताव) तैयार करना होता है जो उसकी स्थानीय परिस्थितियों, संसाधनों और महत्वकांक्षाओं के स्तरों के लिए उपयुक्त हो।

शिमला शहर का चयन भारत सरकार की स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता के तीसरे दौर के अंतर्गत 28 जून, 2017 में हुआ था। इस दौर मे शिमला के अतिरिक्त 29 अन्य स्मार्ट सिटीज का भी चयन हुआ था। जनवरी, 2018 में शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड का पंजीकरण भारतीय क0 अधिनियम, 2013 के अंतर्गत किया गया। तदोपरान्त कार्यालय को स्थापित कर शुरू किया गया एंव कर्मचारियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया इत्यादि सभी औपचारिकताएं आरम्भ की गई। आरम्भ में परियोजना प्रबंध सलाहकार (पी0 एम0

सी0) को नियुक्त करने की प्रक्रिया की गई जिसके अंतर्गत निविदाएं आमन्त्रित की गई। मगर उनमें से एक कम्पनी जो अयोग्य पाई गई थी, वह माननीय उच्च न्यायालय में चली गई। शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने अपना पक्ष सभी तर्कों सहित रखा, जिसके फलस्वरूप उस कम्पनी को कोई अंतरिम राहत प्राप्त नहीं हुई। इसी दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निर्णय लिया कि देश की अन्य कुछ स्मार्ट सिटीज की तर्ज पर शिमला स्मार्ट सिटी भी कार्यों को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के बिना हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों/एंजेंसियों के माध्यमों से कार्यन्वयन किया जाए।

शिमला स्मार्ट सिटी प्रंबध निदेशक–सह–मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में कार्यरत है जिसके कार्यों की रूपरेखा और निर्देशन के लिए सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया है।

शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटिड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा पारित प्रस्तावों पर विभिन्न कार्यान्वयन विभागों अथवा एंजैसियों के माध्यम से कार्य करवाना सुनिश्चित करती है।

शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 2,905,97 करोड़ रूपये है। शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के कुल वित्तीय परिव्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रम संख्या	घटक	कुल परियोजना लागत (रूपये करोड़ में)
1.	क्षेत्र आधारित विकास	2,531.59
i)	पुनर्विकास प्रस्ताव	1,247.91
ii)	रेट्रोफिटिंग प्रस्ताव	1,283.68
2.	पैन–सिटी प्रस्ताव	197.17
3.	प्रशासनिक एंव कार्यालय निधि (एस0पी0वी0+पी0एम0सी0)	177.21
	कुल योग	**2,905.97**

उपर्युक्त परियोजना लागत के लिए धनराशि का निम्न प्रकार से प्रावधान किया जाना प्रस्तावित थाः–

क्रम संख्या	निधि स्त्रोत	राशि (रूपये करोड़ में)
1.	एस0पी0वी0 फंड (केन्द्र+राज्य का अनुदान)	987.11
2.	अभिसरण निधि	315.91
3.	सार्वजनिक निजी भागीदारी	879.52
4.	नगर निगम बांड	167.86
5.	स्व वित+ऋण	403.47
6.	स्पैशल पर्पस विहिकल (एस0पी0वी0) लाभ राशि	152.10

अभी तक शिमला स्मार्ट सिटी को 383 करोड़ रूपये (केन्द्रीय भाग 194 करोड़ और राज्य भाग 189 करोड़ रूप्ये) की राशि जारी की गई है। इस राशि में से लगभग 214

करोड़ रूप्ये की राशि खर्च की जा चुकी है। शिमला स्मार्ट सिटी के अर्न्तगत किए जा रहे परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

सक्रिय कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं/घटक		
विवरण	**घटकों की संख्या**	**रकम (करोड़ रूपए में)**
(A) परियोजना पूर्ण कर दी गई	34	45.83
(B) अवार्डेड/कार्यान्वयन के तहत परियोजना	71	298.44
(C) निविदांए आमंत्रित कर दी गई	17	117.73
I कुल (A+B+C)	**122**	**462.00**
प्रस्तावित परियोजनाएं		
(D) डी0पी0आर/आकलन तैयार कर दिया गया है।	28	169.00
(E) डी0पी0आर/आकलन तैयार किया जा रहा है	08	22.59
II कुल (D+E)	**36**	**191.59**
कुल (I + II)	**158**	**653.59**
(F) कार्यान्वयन के लिए चिहिन्त की गई परियोजनांए/घटक	07	45.54
कुल योग	**165**	**699.13**

शिमला स्मार्ट सिटी के अर्न्तगत आने वाले कार्यों का बहुतायत भाग वन विभाग से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा शिमला शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्यो पर प्रतिबन्ध है। उपरोक्त सभी कठिनाइयों और अन्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए शिमला स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने परियोजना व्यय को निर्धारित किया है। विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन लक्षित उद्देश्यों के अनुरूप किया जा रहा है।

<u>क्षेत्र आधारित विकासः</u>

जैसा कि विदित है कि सर्कुलर रोड शिमला शहर की जीवन रेखा है। समय के साथ–साथ बढ़ती आबादी तथा पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही के कारण ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है और जाम की समस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके निवारण के लिए सड़क मार्गों का निर्माण एंव उन्हें चौड़ा करके शहर में वाहनों की आवाजाही में सुगमता लाना शिमला स्मार्ट सिटी के प्रमुख कार्यों में से एक है। जिसके अर्न्तगत लोक निर्माण विभाग द्वारा 7 कि0 मी0 सड़क चौड़ी की जा चुकी है । शिमला शहर पैदल चलने वालों के लिए ख्याति प्राप्त है, इसलिए सर्कुलर रोड के साथ पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए 8.3 कि0 मी0 पैदल मार्ग बनाये जा चुके है। संजौली में बारहमासी पैदल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर चौराहों को चौड़ा किया जा रहा है। जिन स्थानों पर ट्रैफिक

बहुत ज्यादा है जैसे–लक्कड़ बाजार बस स्टैंड, लिफ्ट के समीप, विकास नगर, ऑकलैण्ड के पास, डी0डी0यू0 हॉस्पिटल के पास, वहां पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर लिफ्ट तथा ऐस्कलैटर की स्थापना भी की जा रही है। तहबाजारियों के पुर्नवास के लिए वेंडिग जोन का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोगों एवं वाहनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए ढली में हि0 प्र0 रोड एंव इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट निगम के माध्यम से 48 करोड़ रू0 की लागत से टनल का निर्माण किया जा रहा है। शहर को सुंदर बनाने के लिए कुछ स्थानों जैसे रिज पर मरीना होटल के पास, टका बैंच के पास सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है, छोटा शिमला में सचिवालय के पास भित्ति चित्र लगाए गए हैं तथा वर्टिकल गार्डन लगाए जा रहे हैं। शहर में 6 स्थानों पर इ–टॉयलट स्थापित किए गए हैं।

<u>पैन सिटी प्रस्तावः</u>

इसके अन्तर्गत शिमला शहर में विभिन्न स्थानों पर जैसे IGMC**,** बस स्टैंड, विकासनगर, इत्यादि स्थानों पर पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। पार्किंग का निर्माण, शहर की सफाई के लिए यांत्रिक वाहनों का प्रयोग, शहर के पर्यावरण को बचाने के लिए ई–बसें एंव चार्जिंग स्टेशनों का प्रावधान, शहर मे सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए क्लोज सर्किट कैमरों को पुलिस विभाग के माध्यम से स्थापित करना, विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से शिक्षा देने हेतू स्मार्ट स्कूलों का निर्माण इत्यादि प्रमुख है। इसके इलावा ऊर्जा की बचत करने के लिए सरकारी भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जा रही है जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत उपयोगी है।

स्मार्ट सिटी के अर्न्तगत कंमाड और कन्ट्रोल सेन्टर स्थापित किया जाएगा जिसका संचालन हिमाचल प्रदेश सचिवालय में स्थित नियंत्रण कक्ष से किया जाएगा। कंमाड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के माध्यम से कई सेवाओं जैसे–वन सिटी वन ऐप, स्मार्ट सलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट, वाटर स्काडा (एकीकरण), सिवरेज स्काडा (एकीकरण), स्मार्ट लाईटिग/मीटरिग (एकीकरण), रियल टाईम एयर क्वालिटी मोनिट्रिंग (एकीकरण), सार्वजनिक परिवहन सूचना (एकीकरण), सिटी शहर निगरानी प्रणाली, जीपीएस आधारित आपातकालीन प्रतिक्रिया (एमडीटी), भूस्खलन अलर्ट इत्यादि के संचालन में सहायता मिलेगी। स्मार्ट सिटी के कार्यों का निष्पादन स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निर्धारित विभागों से करवाया जा रहा है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	विभाग	संख्या	राशि (ए0 ए0 एण्ड इ0 एस0) रकम रूपये करोड़
1	लोक निर्माण विभाग (फोर्थ सर्कल)	64	225.33
2	लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय उच्च मार्ग)	8	33.35
3	लोक निर्माण विभाग (यांत्रिक विंग)	4	13.85
4	रोपवें और रैपिड ट्रासंपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	22	68.63
5	आवास और शहरी विकास प्राधिकरण	13	77.54
6	नगर निगम शिमला	20	45.21
7	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटिड	7	27.24
8	ऊर्जा विकास एजेंसी	3	14.95
9	राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम	2	8.31
10	सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग	2	41.71
11	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	12	44.8
12	स्वास्थ्य विभाग	1	3.00
13	युवा सेवांए और खेल	1	21.66
14	हि0 प्र0 रोड एंव इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1	48.00
15	भूमि अधिग्रहण	1	0.00
16	पुलिस विभाग	2	0.55
17	हिमाचल पथ परिवहन निगम	1	15.00
18	राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड	1	10.00
	कुल	**165**	**699.13**

शिमला स्मार्ट सिटी के विभिन्न कार्य सरकारी विभागों द्वारा करवायें जा रहे है। सम्बंधित विभागों द्वारा यह कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप किए जा रहे है अतः इन कार्यों की गुणवता कम होने का संशय नहीं रह जाता। उपरोक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए स्मार्ट सिटी के किसी भी कार्य में कोताही नहीं बरती गई है।

हांलाकि मैं फिर माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यदि इन कार्यों को करने मे कोई अनियमितता ध्यान में आती है या लायी जाती है तो उसकी निष्पक्ष जाच करवाई जाएगी।

.....